शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 48 वां वर्ष

ई-पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

धवर्ष 48 अंक-23 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पर्जीकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 05-12 जून 2023 मूल्य पांच रूपये

मुख्यमन्त्री की चुनौती पर पत्र बम पहुंचा ई.डी. में

- जयराम और बिंदल ने की थी जांच की मांग
- सुक्खू ने कहा था ई.डी. से करवा ले जांच
- प्रबोद्ध सक्सेना है पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष और मीणा है एम.डी.
- शांग-टांग का काम कर रही पटेल इंजीनियरिंग पहले से ही चल रही है ई.डी के निशाने पर

शिमला/शैल। जिस बेनामी पत्र बम ने प्रदेश की राजनीति को पिछले दिनों हिला कर रख दिया था उसकी जांच करवाये जाने की मांग नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने अलग-अलग ब्यानों में की थी। इस मांग की प्रतिक्रिया में मुख्यमन्त्री सुक्खू ने भी खुली चुनौती देते हुये कहा था कि भाजपा चाहे तो इसकी जांच ई.डी. या सी.बी.आई. से करवा ले। यह बेनामी पत्र प्रधानमन्त्री को संबोधित था। इसमें अन्य आरोपों के साथ किन्नौर में निर्माणाधीन चल रही 450 मेगावाट की शांग-टांग परियोजना में भ्रष्टाचार होने की भी आरोप है। वर्ष 2012 से इस परियोजना का निर्माण कार्य पटेल इंजीनियरिंग कम्पनी के पास है। यह काम जयराम सरकार के कार्यकाल में ही पूरा हो जाना चाहिये था लेकिन हो नही पाया। क्योंकि शायद कम्पनी परियोजना में कुछ डेविएशन चाहती थी। इस डेविएशन के कारण निर्माण लागत में बढौतरी होनी थी इसलिए यह मामला तब कानूनी राय के लिये शायद अधिवक्ता भोगल के पास भेजा गया था। इस पर शायद कानूनी राय यह आयी थी कि इसकी शर्तो में बदलाव नहीं किया जा सकता और यह मामला उसी स्टेज पर रूक गया था।

अब सरकार बदलने के बाद यह मामला फिर उठा। डेविएशन और उसके कारण लागत बढ़ने तथा परियोजना पूरी होने का समय बढ़ाने का प्रकरण फिर चर्चा में आया। कहा जा रहा है कि कानूनी राय को नजरअन्दाज करते हुये कम्पनी के आग्रह पर डेविएशन और लागत बढ़ने की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। यह होने के बाद कम्पनी को दो सौ करोड़ की राशि भी जारी कर दिये जाने की चर्चा है। यह डेविएशन किस स्तर पर हुई और इससे निर्माण लागत में कितनी बढ़ौतरी होगी तथा परियोजना पूरी होने में और कितना समय लगेगा यह सब जांच के विषय हैं। स्मरणीय है कि पटेल इंजीनियरिंग कम्पनी पर जम्मू कश्मीर में चल रही कीरु परियोजना को लेकर उठी कुछ शिकायतों पर ई.डी. पहले ही छापेमारी कर चुकी है। शायद इस परियोजना पर सत्यपाल मलिक ने बतौर राज्यपाल अपने कार्यकाल में कुछ सवाल उठाये थे और मामला ई.डी. तक जा पहुंचा था। इसी पृष्ठभूमि में अब-जब शांग-टांग परियोजना को लेकर यह सवाल उठे हैं कि कानूनी राय को नजरअन्दाज करके डेविएशन अनुमोदित कर दी गयी है तो मामला स्वत: ही गंभीर हो जाता है।

फिर इस मामले में तो स्वयं मुख्यमंत्री ने जयराम को चुनौती दी है कि वह चाहे तो ई.डी. से जांच करवा ले। मुख्यमंत्री की इस ललकार के बाद प्रधानमन्त्री से यह मामला ई.डी. तक जा पहुंचा है। इस पर किसी राजनीतिक ज्यादती का भी आरोप नहीं लगाया जा सकता। इस जांच में पावर कारपोरेशन की पूरी कार्यप्रणाली पहले दिन से लेकर आज तक जांच के दायरे में आ जायेगी। यही नहीं पत्र बम्ब में लगे अन्य आरोपों की जांच से पूरी सरकार की कार्यप्रणाली केन्द्र में आ जायेगी और विपक्ष को फिर एक मुद्दा मिल जायेगा। क्योंकि पत्र में लगाये गये आरोपों के घेरे में मुख्यमंत्री के अपने कार्यालय और विभाग आ जाते हैं। ई.डी. के शिमला कार्यालय तक पहुंच चुके इस मामले से प्रशासन में कई लोगों के हाथ पांव फूलना शुरू हो गये हैं।

क्या प्रदेश वित्तीय आपात की ओर बढ़ रहा है?

- खजाना खाली होने से उठी चर्चा
- भाजपा ने सरकार के हर मोर्चे पर फेल होने का जड़ा आरोप
- हालात न संभले तो सरकार आ जायेगी संकट में

शिमला/शैल। सुक्खू सरकार वित्तिय मोर्चे पर जिस तरह से फेल होती जा रही है उससे विपक्षी दल भाजपा को सरकार के खिलाफ एक बड़ा हथियार मिल गया है। सरकार इस असफलता के लिए केन्द्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है कि उसने कर्ज लेने की सीमा में कटौती करके यह हालात पैदा कर दिये हैं। लेकिन दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने यह खुलासा करके की सुक्खू सरकार अब तक सात हजार करोड़ का कर्ज ले चुकी है एक अलग ही तस्वीर लोगों के सामने रख दी है जिसका सरकार कोई जवाब नहीं दे पा रही है। क्योंकि कर्ज सीमा कटौती करने से पहले यह सीमा 14,500 करोड़ की थी। अभी सरकार को बने हुये कुल छ: माह का समय हुआ है। सुक्खू सरकार अभी पहला ही बजट लायी है और इसी के पहले दो माह में खजाना खाली होने, कई कर्मचारियों को वेतन न मिल पाने और कोषागार हर रोज एक घन्टा बन्द रखने के हालात पैदा हो जाये तो इसके लिये केन्द्र पर दोष देने की बजाये अपने वित्तीय प्रबंधको की नीयत और नीति पर ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि जितना कर्ज इसी दौरान ले लिया गया है उससे स्पष्ट हो जाता है कि यह सरकार केवल कर्ज पर ही आश्रित होकर चल रही थी। जिस तरह से इस सरकार ने पहले ही दिन डीजल के दाम बढ़ाने का तोहफा जनता को दिया था उसी से स्पष्ट हो गया था कि सरकार ईमानदार सलाहकारों के हाथ में नहीं है। क्योंकि इन्हीं सलाहकारों की राय पर श्रीलंका जैसे हालात पैदा होने की चेतावनी दी गयी थी जबकि सरकार का अपना एक भी कदम इस चेतावनी के अनुरूप नही था।

आज वित्तीय संकट का जो आकार हो चुका है उसके अनुरूप संसाधन जुटाने का एक भी प्रयास नही है। जिन परियोजनाओं में हिस्सेदारी बढ़ाकर संसाधनों की उम्मीद की जा रही है वह सारे मामले अदालतों तक पहुंचेंगे यह स्वभाविक है। जिन संसाधनों से बिना किसी दूसरे के दखल के पैसा जुटाया जा सकता है उस ओर कोई सलाहकार सोच ही नही पा रहा है। मौद्रीकरण का जो सूत्र केन्द्र ने पकड़ा था उस ओर प्रदेश में कोई ध्यान ही नही दिया जा रहा है। इस परिदृश्य में विपक्ष सरकार पर लगातार हावी होता जायेगा।

वित्तीय प्रबंधन की असफलता

शेष पृष्ठ 8 पर.....

राज्यपाल ने एआईएए अवार्ड प्रदान किए

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शिमला के ऐतिहासिक कालीबाड़ी हाल में अखिल भारतीय कलाकार संघ द्वारा आयोजित 68वीं वार्षिक अखिल भारतीय नाटक एवं नृत्य प्रतियोगिता के समापन समारोह

की अध्यक्षता करते हुए कहा कि समाज निर्माण में कला एवं कलाकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि कला हमें जीवंत बनाती है और यह हर व्यक्ति के जीवन का अभिन्न अंग है।

उन्होंने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले छह दशकों में संघ ने विभिन्न आयोजनों के माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयास न केवल समाज को दिशा देते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का कारण बनते हैं। उन्होंने कहा कि यह संस्था जिस भावना से कला के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने का कार्य कर रही है, वह प्रशंसनीय है। उन्होंने सभी कलाकारों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई दी।

राज्यपाल ने कहा कि नृत्य और नाटक हमेशा से मानव सभ्यता का अभिन्न अंग रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये अभिव्यक्ति के ऐसे शक्तिशाली माध्यम हैं, जो भाषा के मोहताज नहीं है। इनके उपयोग से भावनाओं, कहानियों और विचारों को प्रभावी ढंग से व्यक्त किया जाता है। उन्होंने कहा कि कला के इन रूपों में हमें विभिन्न परिदृश्यों से रू-ब-रू करने, हमारी भावनाओं को जगाने और हमारी कल्पना को व्यापक बनाने की क्षमता है।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रशांत भगत को सुदर्शन गौड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लोकिंदर त्रिवेदी को बलराज साहनी अवार्ड तथा आशीष पिल्लई और मीनू चड्ढा को गोपी कृष्ण राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया।

अखिल भारतीय कलाकार संघ के अध्यक्ष रोहिताश्व गौड़ ने राज्यपाल का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि शिमला में 6 से 10 जून तक आयोजित इस प्रतियोगिता में 20 राज्यों के लगभग 1000 कलाकारों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि संघ वर्ष 1955 में अस्तित्व में आया और अब तक देश भर में संघ द्वारा कई नाटक और नृत्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा चुका है। इस अवसर पर संघ की उपाध्यक्ष डॉ. रेखा गौड़ ने राज्यपाल को सम्मानित किया।

राज्यपाल से थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने भेंट की

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से राजभवन में थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे (पी.वी.एस.

एम., ए.वी.एस.एम., वी.एस.एम., ए.डी.सी.) ने भेंट की।

यह एक शिष्टाचार भेंट थी। इस अवसर पर राज्यपाल ने उन्हें हिमाचली टोपी व शॉल के साथ स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया।

राज्यपाल को थल सेनाध्यक्ष ने सेना से सम्बंधित विभिन्न मुद्दों पर जानकारी दी। शिव प्रताप शुक्ल और जनरल मनोज पांडे ने क्षेत्र की सुरक्षा और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की।

आर्मी ट्रेनिंग कमांड (आरट्रेक) के जनरल ऑफिसर कमांडिंग -इन-चीफ, लेफ्टिनेंट जनरल एस.एस. महल भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

प्रदेश सरकार सेब सीजन को सफल बनाने के लिए प्रयासरत:जगत सिंह नेगी

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में सेब का उत्पादन किसानों-बागवानों

की आय और प्रदेश की आर्थिकी का मुख्य स्रोत है। प्रदेश सरकार राज्य में आगामी सेब सीजन के लिए सभी प्रकार की तैयारियां पूर्ण करने की दिशा में कार्य कर रही है।

यह बात बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने पराला सब्जी मण्डी तथा सीए स्टोर एवं सब्जी मण्डी शिलारू के निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।

जगत सिंह नेगी ने बैठक के दौरान संबद्ध विभागों के अधिकारियों को समय पर सभी प्रबंध पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने पराला से छैला सड़क को बेहतर बनाने के निर्देश भी दिए।

इसके अतिरिक्त उन्होंने पराला में आधुनिक फल प्रसंस्करण संयंत्र तथा प्रदेश में विभिन्न सब्जी मण्डियों के निर्माण कार्यों की जानकारी भी ली।

इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड के प्रबंध निदेशक नरेश ठाकुर, हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम के महाप्रबंधक हितेश आजाद तथा जल शक्ति विभाग, लोक निर्माण विभाग, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड और हिमऊर्जा के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

पैरा कर्मियों की सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध प्रदेश सरकार: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सामाजिक सरोकार को अधिमान देते हुए राज्य के कर्मचारियों और पैरा कर्मियों के कल्याण के लिए कई कदम उठाये हैं। राज्य के विकास में कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका को सम्मान देते हुए सरकार ने सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत लाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। सरकार के इस निर्णय से कर्मठ कर्मचारियों को सेवानिवृति के बाद भी सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होगी।

राज्य के विकास में पैरा कर्मियों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार ने उन्हें वह सम्मान देने का निर्णय लिया जिसके वे हकदार हैं। प्रदेश सरकार ने दैनिक भोगियों की दिहाड़ी को 350 रुपए से बढ़ाकर 375 रुपए किया है, इससे उन्हें अब प्रतिमाह 750 रुपए का लाभ मिल रहा है। कोविड-19 महामारी के चुनौतीपूर्ण समय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के समर्पण और निःस्वार्थ भाव को देखते हुए सरकार ने उनके मानदेय को 9000 रुपये से बढ़ाकर 9500 रुपये प्रति माह किया है। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को भी 6100 रुपये से बढ़ाकर 6600 रुपये किया है। आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 4700 रुपये से बढ़ाकर 5200 रुपये किया है।

स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और आशा कार्यकर्ताओं की मानवीय सेवा से राज्य सरकार भलीभांति परिचित है। राज्य सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में 500 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि की। अब आशा कार्यकर्ताओं को 5200 रुपये का मासिक मानदेय मिल रहा है। सिलाई शिक्षक, नए प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य सरकार ने उनके मानदेय में 500 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि की है। राज्य सरकार ने उनके मानदेय को 3500 रुपये से बढ़ाकर 4000 रुपये प्रति माह कर किया है।

नैनिहालों को पोषणयुक्त भोजन परोसने वाले मिड-डे मील कार्यकर्ताओं का अब सरकार ने भलीभांति ख्याल रखते हुए उनके मानदेय को 3500 रुपए से बढ़ाकर 4000 रुपए प्रतिमाह किया है। शिक्षा विभाग में कार्यरत जल रक्षकों के मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि भी की गयी है। अब जल रक्षकों को 3900 रुपए के बजाये 4400 रुपए प्रति माह मिल रहे हैं। यह निर्णय उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रहा है।

राज्य सरकार पैरा श्रमिकों की विभिन्न श्रेणियों को सम्मानजनक पारिश्रमिक प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। जलरक्षकों, बहुउद्देश्यीय कर्मियों, पैरा फिटरों और पंप संचालकों के मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि की गयी है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने पंचायत चौकीदारों, राजस्व चौकीदारों, एसएमसी शिक्षकों और लम्बरदारों के मानदेय में भी सम्मानजनक वृद्धि की है। आउटसोर्स कर्मचारियों के योगदान को देखते हुए सरकार ने उनके लिए न्यूनतम वेतन प्रति माह 11,250 रुपये निश्चित किया है।

हाल ही में आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में सरकार ने अंशकालीन पंचायत चौकीदारों के मासिक मानदेय को 6200 रुपए से बढ़ाकर 6700 रुपए करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय 01 अप्रैल, 2023 से लागू होगा। इस निर्णय ने राज्य के 3226 अंशकालिक पंचायत चौकीदारों लाभान्वित होंगे। प्रदेश के विकास में कर्मचारियों और पैरा वर्कर्ज़ को सहभागी बनाते हुए राज्य सरकार उनके कल्याण और उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है।

मुख्यमंत्री से शिमला व्यापार मण्डल के प्रतिनिधि मंडल ने भेंट की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से ओक ओवर में शिमला व्यापार मंडल का प्रतिनिधि मंडल विधायक हरीश जनारथा की अध्यक्षता में मिला। प्रतिनिधि मंडल ने हिमाचल प्रदेश होर्डिंग और प्रोफिटियरिंग प्रिवेंशन आदेश 1977, एचपी कमोडिटी प्राइस मार्किंग और डिस्प्ले आर्डर 1977 तथा एचपी ट्रेड आर्टिकल (लाइसेंसिंग और कंट्रोल) आदेश 1981 को हटाने की मांग की।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने व्यापार मंडल को उचित कारवाई का आश्वासन दिया। इस अवसर पर व्यापार मंडल के अध्यक्ष हरजीत कुमार, महासचिव नितिन सोहल, कोषाध्यक्ष दीपक अग्रवाल, प्रदीप कुमार भुज्जा, नरेश कंधारी, राकेश पुरी, अजय सरना तथा तरुण राणा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

किरतपुर-मनाली राजमार्ग के किनारे एचपीटीडीसी खोलेगा तीन होटल

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ओक ओवर में हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि निगम भविष्य में किरतपुर-मनाली फोर लेन राजमार्ग के किनारे तीन अतिविशिष्ट होटल खोलेगा। इससे पर्यटकों और अन्य यात्रियों को अत्याधुनिक सुविधाएं प्राप्त होंगी। उन्होंने कहा कि ये होटल आधुनिक सुविधाओं से सुस्सजित होंगे और इसका उद्देश्य राज्य में पर्यटकों को बेहतरीन अनुभव प्रदान करना है। इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए एक सलाहकार द्वारा एक अध्ययन भी किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि फोर लेन राजमार्ग के आरम्भ होने से क्षेत्र में पर्यटकों की आमद में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पर्यटकों को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएगी ताकि उन्हें प्रदेश में यात्र का सुखद अनुभव प्राप्त हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन के बुनियादी ढांचे और सेवाओं के विस्तार की दिशा में सरकार प्रयास कर रही है। इससे न केवल पर्यटन व्यवसाय को सम्बल मिलेगा बल्कि स्थानीय आबादी के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हाल ही में मंत्रिमण्डल की बैठक में किरतपुर-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ बिलासपुर जिला के बगेड़, मंडी जिला के नेरचौक और कुल्लू जिला के भुंतर में तीन नए राजमार्ग-सह-पर्यटन पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि इन पुलिस स्टेशनों को क्रियाशील करने के लिए कर्मचारियों की आवश्यक भर्ती भी की जाएगी, जिसका उद्देश्य पर्यटकों की आवश्यकता को पूरा करना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

बैठक के दौरान, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक अमित कश्यप ने निगम द्वारा क्रियान्वित की रही परियोजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

प्रदेश सरकार सहकारी बैंकों को सुदृढ़ करने के लिए हरसम्भव सहायता प्रदान करेगीः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड द्वारा आयोजित स्पार्क-2023 कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बैंक के नए चिन्ह (लोगो) का अनावरण किया। इसके अलावा उन्होंने बैंक की इंटरनेट बैंकिंग सुविधा एकेडमी फॉर एग्रीकल्चर एंटरप्रिन्योरशिप डिवेलपमेंट फॉर ग्रोथ एंड एम्पावरमेंट और नई वेबसाइट का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने बैंक का विजन डाक्यूमेंट भी जारी किया। उन्होंने बैंक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शाखा कार्यालयों को पुरस्कार भी प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने भविष्य की चुनौतियों के लिए एचपीएससीबी द्वारा तैयार रहने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि राज्य सरकार सहकारी बैंकों को हरसंभव सहायता प्रदान कर सुदृढ़ करेगी। उन्होंने कहा कि बैंक डिजिटल तकनीकयुक्त होने चाहिए और उपभोक्ताओं को आधुनिक तकनीक का उपयोग कर बैंकिंग सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। उन्होंने कहा

कि सहकारी बैंकों की कार्यप्रणाली के विस्तार के लिए छह महीने के भीतर सुधारों को लागू किया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि सहकारी बैंकों को भूमि खरीदने के लिए प्राथमिकता के आधार पर हिमाचल प्रदेश मुजारियत एवं भू-सुधार अधिनियम 1972 की धारा 118 के तहत अनुमतियां दी जाएंगी।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान सरकार का पहला बजट व्यवस्था परिवर्तन का प्रतीक है, जिसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक को इन पहलों के क्रियान्वयन में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। राज्य सरकार निर्धन परिवार के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए 20 लाख रुपए तक का ऋण एक प्रतिशत ब्याज की दर से उपलब्ध करवाने की योजना बना रही है ताकि संसाधनों के अभाव में कोई भी शिक्षा से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना की योजना के लिए सहकारी बैंक को प्रमुख बैंक बनाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश अपने अधिकारों के लिए मजबूती से संघर्ष करेगा। उन्होंने कहा कि राज्य में 12000 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है लेकिन हिमाचल प्रदेश को राज्य के हिस्से के रूप में केवल 12 प्रतिशत बिजली मिल रही है, जो राज्य के लोगों के साथ अन्याय है। पे-बैक अवधि पूरी कर चुकी जलविद्युत परियोजनाओं में रायल्टी बढ़ाने का मामला केंद्र सरकार के समक्ष उठाया गया है। निश्चित अवधि समाप्त होने के बाद केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा बनाई गयी पनबिजली परियोजनाएं हिमाचल को वापस मिलनी चाहिए। शानन परियोजना को वापस लेने के लिए बातचीत हो चुकी है और वर्तमान राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश के हितों की लड़ाई लड़ने को तैयार है। उन्होंने कहा कि जल उपकर हिमाचल का अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार आगामी चार वर्षों में हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हरित उद्योगों को बढ़ावा देगी, जिसमें पर्यटन, जल ऊर्जा, आईटी, डाटा सेंटर और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र शामिल होंगे।

उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हिमाचल प्रदेश में सहकारिता आंदोलन के महत्व पर प्रकाश डाला, जिसे देश भर में पहचान मिली है। उन्होंने बताया कि प्रथम सहकारी सभा की स्थापना वर्ष 1892 ऊना जिला के पंजावर में की गयी थी जो उनके विधानसभा क्षेत्र हरोली के अंतर्गत आता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सहाकारी सभा के माध्यम से शुरू किए गए सहकारी बैंक अब राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में काम कर रहे हैं। व्यक्यिों द्वारा सहकारी समितियों की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के उदाहरणों को स्वीकार करते हुए उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार सहकारी सभाओं को एक नए जन आंदोलन में बदलने के लिए सुधारात्मक उपाय कर रही है। अग्निहोत्री ने अधिकारियों से बैंक की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखकर कार्य करने का आग्रह किया।

उन्होंने राज्य के विकास में कर्मचारियों द्वारा सहयोग प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने हिमाचल प्रदेश को आर्थिक रूप से अस्थिर करने के प्रयासों और राज्य को वित्तीय सहायता प्रदान करने में बाधाएं उत्पन्न करने पर भी चिंता व्यक्त की।

एचपीएससीबी के अध्यक्ष देवेंद्र श्याम ने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए राज्य के विकास में सहयोग देने के लिए बैंक की प्रतिबद्धता पर बल दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में बैंक की सफलता, नए कीर्तिमान स्थापित करने और जनता को लाभान्वित करने के लिए राज्य सरकार की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने पर प्रकाश डाला। इसके अतिरिक्त बैंक राज्य सरकार के नेतृत्व में हरित पहल में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। देवेंद्र श्याम ने बैंक की विविध गतिविधियों के बारे में भी जानकारी साझा की। उन्होंने बैंक की ओर से ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 2 करोड़ रुपए का चेक भेंट किया।

इस अवसर पर मुख्य संसदीय सचिव मोहन लाल ब्राक्टा, विधायक नंद लाल, हरीश जनारथा, कुलदीप सिंह राठौर, अजय सोलंकी, चंद्रशेखर, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (आईटी और नवाचार) गोकुल बुटेल, जोगिंद्रा केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष मुकेश शर्मा, हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष संजय चौहान, सचिव कृषि राकेश कंवर भी अन्य गणमान्य व्यक्तियों सहित उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के समक्ष शानन परियोजना हिमाचल को सौंपने की पैरवी की

25 मैगावॉट से कम क्षमता की जल विद्युत परियोजनाओं के लिए योजना बनाने का आग्रह किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उन्होंने प्रदेश के दो दिवसीय प्रवास पर आये केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के.सिंह के समक्ष ऊर्जा क्षेत्र से सम्बंधित विभिन्न मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। केंद्रीय मंत्री ने इन सभी मुद्दों को समयबद्ध हल करने के प्रति आश्वस्त किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से शानन जल विद्युत परियोजना को हिमाचल प्रदेश को हस्तातंरित करने के लिए समयबद्ध प्रक्रिया पूर्ण करने का आग्रह किया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को शानन परियोजना के स्वामित्व से सम्बंधित विभिन्न पहलुओं से अवगत करवाया। केंद्रीय मंत्री को यह भी अवगत करवाया गया कि शानन परियोजना के स्वामित्व का अधिकार पंजाब सरकार के पास नहीं है क्योंकि यह परियोजना केवल पट्टे पर पंजाब को दी गयी थी और पट्टे की यह अवधि मार्च, 2024 में पूरी हो रही है।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के हितों के दृष्टिगत उन्होंने केंद्र सरकार से प्रदेश में 25 मेगावॉट क्षमता से कम की पन विद्युत परियोजनाओं को सुविधा प्रदान करने के दृष्टिगत इनके ढांचागत विकास के लिए एक योजना बनाने का भी आग्रह किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने परियोजना निर्माताओं के हितों के दृष्टिगत इस बारे में शीघ्र ही एक योजना आरम्भ करने का आश्वासन दिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्री के साथ निःशुल्क विद्युत बिक्री से सम्बंधित विभिन्न मामलों पर भी चर्चा की गयी जिस पर उन्होंने सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सौर विद्युत के अनुरूप हिमाचल प्रदेश को हरित हाईड्रोजन के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने का आग्रह किया ताकि हरित हाईड्रोजन उत्पादन क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाई जा सके। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को बताया कि प्रदेश सरकार राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सुविधाएं प्रदान कर रही है। वर्ष 2023-24 के लिए प्रदेश में 500 मैगावॉट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

कमजोर वर्गों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही प्रदेश सरकारः डॉ. शांडिल

शिमला/शैल। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है और इस दिशा में अनेक कदम उठाए गए हैं।

उन्होंने बताया कि इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना के तहत लाहौल-स्पिति में 840 महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह की दर से राशि प्रदान की गयी है। मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना के तहत लगभग 7000 विधवाओं और एकल नारियों को 1.50 लाख रूपए की राशि प्रदान की जाएगी।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अनाथ और विशेष रूप से विकलांग बच्चों, निराश्रित महिलाओं और बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना शुरू की है। इस योजना के अन्तर्गत सरकार ने 6000 अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया है। योजना के तहत अनाथ बच्चों की शिक्षा, छात्रावास, व्यवसायिक प्रशिक्षण व कौशल विकास का व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने बताया कि अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सड़क सुविधा, पेयजल, बिजली व अन्य विभिन्न विकास कार्य किए जा रहे हैं। इस अवसर पर अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के निदेशक प्रदीप ठाकुर, महिला एवं बाल विकास विभाग की अतिरिक्त निदेशक एकता काप्टा व अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

प्रदेश के पांच कस्बों में होगी बेहतर सीवरेज सुविधाः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। स्वच्छता के लिए सीवरेज प्रणाली बेहद महत्वपूर्ण है। पेयजल सुविधा को सदैव प्राथमिकता दी जाती है लेकिन विकास में सीवरेज प्रणाली की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। दूषित पानी को पुनः उपयोग में लाने के लिए उसका ठीक से एकत्रण तथा उपचार आवश्यक है। ऐसा न करने की स्थिति में गंभीर जल प्रदूषण की समस्या की संभावना होती है।

जल एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है और इसका कुशलता से उपयोग किया जाना चाहिए। वर्तमान राज्य सरकार ने राज्य के पांच कस्बों में पेयजल और स्वच्छता सेवाओं में सुधार करने का निर्णय लिया है, जिनमें मनाली, बिलासपुर, पालमपुर, नाहन और करसोग शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हाल ही में उपरोक्त कस्बों में बेहतर सीवरेज सुविधाओं को विकसित करने तथा मनाली और पालमपुर में पेयजल आपूर्ति में सुधार के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा फ्रांसीसी विकास एजेंसी, एजेंसे फ्रैंकेइस डी डेवलपमेंट के साथ 817.12 करोड़ रुपये की परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि एएफडी द्वारा 612 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे जबकि राज्य सरकार 204.85 करोड़ रुपये प्रदान करेगी। परियोजना के तहत लाभार्थियों को इन पांच कस्बों में सीवरेज के कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को अत्याधुनिक तकनीकों के साथ डिजाइन किया जाएगा, जिससे कृषि और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए अपशिष्ट का पुनः उपयोग किया जा सके। परियोजना का उद्देश्य जल स्रोतों की पर्यावरणीय स्थिति में सुधार करना, जल जनित रोगों को कम करना, स्थानीय नियमों और अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुसार गुणवत्तापूर्ण स्वच्छता सुविधाओं का प्रबंधन करना और पेयजल व स्वच्छता क्षेत्र में वित्तीय स्थिरता लाना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रथम चरण में 425.85 करोड़ रुपये में से एएफडी द्वारा 340 करोड़ रुपये का वित्तपोषण किया जाएगा। दूसरे चरण में 371 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत में से एएफडी 272 करोड़ रुपये प्रदान करेगी। परियोजना तीन वर्ष के भीतर लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस परियोजना का दूसरा चरण पहले चरण के शुरू होने के 18 महीने बाद आरम्भ होगा।

यह परियोजना राज्य के इन कस्बों के लोगों को सर्वोत्तम स्वच्छता सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में प्रवेश के लिए 16 जुलाई को आयोजित की जाएगी परीक्षा

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा 16 जुलाई, 2023 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय चयन परीक्षा-2023 का आयोजन करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में अधिसूचित अनुसूचित जनजाति वर्ग से सम्बंधित प्रार्थी इसमें भाग ले सकते हैं। इसके लिए प्रार्थी की आयु 01 अप्रैल, 2023 तक 10 से 13 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। प्रार्थी ने शैक्षणिक सत्र 2022-23 के दौरान किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से पांचवीं की परीक्षा उर्तीण की हो। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में कक्षा छठी के लिए कुल 150 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा, जिनमें 75 छात्र और 75 छात्राएं चयनित होंगी।

उन्होंने कहा कि जिला किन्नौर के निचार एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के लिए 30-30 छात्र एवं छात्राएं, जिला चम्बा के भरमौर स्थित होली विद्यालय और पांगी स्थित किलाड़ विद्यालय के लिए 15-15 छात्र एवं छात्राएं, जिला लाहौल-स्पिति के कुकुमसेरी स्थित विद्यालय के लिए 15-15 छात्र एवं छात्राएं चयनित की जाएंगी।

उन्होंने कहा कि प्रार्थी का प्रवेश, चयन प्रक्रिया की मैरिट के आधार पर कांउसलिंग के माध्यम से किया जाएगा। इच्छुक पात्र उम्मीदवार हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला की वैबसाइट https://hpbose.org/Online Services/CET/Eklaya/Instructions. aspX पर 24 जून, 2023 तक निःशुल्क ऑनलाइन आवेदन-पत्र भर सकते हैं।

ज्ञान स्वयं में वर्तमान है, मनुष्य केवल उसका आविष्कार करता है।..... स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

मोदी बनाम राहुल होगा 2024

क्या कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकल्प बन पायेंगे? क्या 2024 में कांग्रेस केन्द्र में सरकार बना पायेगी? क्या एन.डी.ए. से बाहर बैठे राजनीतिक दल कांग्रेस के नेतृत्व में इकटठा हो पायेंगे? क्या एनडीए में टूटन आयेगी? क्या भाजपा कांग्रेस में कोई तोड़फोड़ कर पायेगी? इस समय यह सारे सवाल राजनीतिक विश्लेषकों के लिये अहम बने हुये हैं। क्योंकि राजनीतिक दलों ने 2024 के चुनाव के लिये अभी से विसात बिछानी शुरू कर दी है। इस समय राजनीतिक परिदृश्य मोदी बनाम राहुल और भाजपा बनाम कांग्रेस होता जा रहा है इसमें कोई दो राय नहीं है। यह क्यों हो रहा है इसके लिये 2014 से पूर्व और बाद की परिस्थितियों पर नजर डालना आवश्यक हो जाता है।

देश 1947 में आजाद हुआ। 1950 में संविधान लागू हुआ। 1952 में देश में पहला आम चुनाव हुआ। 1952 से मई 1964 तक स्व.पंडित जवाहर लाल नेहरू बारह वर्ष तक देश के प्रधानमंत्री रहे कांग्रेस सत्ता में रही लेकिन हर चुनाव में जनसंघ और दूसरे दल कांग्रेस को चुनावी चुनौति भी देते रहे। उस समय का मतदाता प्रत्यक्ष रूप से जानता था की आजादी की लड़ाई में किसका क्या योग योगदान रहा है। इतिहास को लेकर जो सवाल आज उठाये जा रहे हैं यह उस समय नही थे। क्योंकि उस समय की जनता उस समय का स्वंय ही इतिहास थी। लेकिन उस दौर में भी जब रियासतों के एकीकरण के बाद कृषि सुधारों की बात आयी थी जब भी सी राजगोपालाचार्य जैसे नेताओं ने इन सुधारों का विरोध किया था। इसी विरोध की पृष्ठभूमि थी कि स्व. इन्दिरा गांधी जी को सत्ता संभालने के लिये कांग्रेस में विघटन तक का सामना करना पड़ा। बैंकों के राष्ट्रीयकरण को उस समय सुप्रीम कोर्ट में स्व.प्रो.बलराज मधोक और अन्य ने चुनौती दी थी। जिसे संविधान में संशोधन करके प्रस्तुत किया गया था। 1964 से 1975 तक का राजनीतिक परिदृश्य किस तरह का रहा है यह भी आम आदमी जानता है। इसी काल में कई राज्यों में संबिद्ध सरकारों का भी गठन हुआ था। आपातकाल के बाद कांग्रेस कितना और विपक्ष कितना केन्द्र की सत्ता पर काबिज रहा है यह सब जानते हैं। 2014 तक कांग्रेस और अन्यों के सत्ता काल में ज्यादा अन्तर व्यवहारिक रुप से नहीं रहा है यह एक स्थापित सत्य है।

1948 से आज तक आर.एस.एस. ने देश में अपने को किस तरह स्थापित किया। कितने उसके सहयोगी संगठन बने और कितने उसकी विचारधारा के स्नातक बनकर निकले हैं उसकी पूरी जानकारी भले ही अधिकांश को न रही हो लेकिन 2014 के बाद आयी भाजपा नीत सरकार के व्यवहारिक पक्ष से सबके सामने आ गयी है। भारत जैसे बहुभाषी और बहुधर्मी देश में इस तरह की विचारधारा की वैचारिक स्वीकारोक्ति कितनी हो सकती हैं यह सामने आ चुका है। क्योंकि विचारधारा के प्रसार के लिए जिस तरह का सामाजिक और आर्थिक परिवेश खड़ा करने का प्रयास किया गया वह अब लगातार अस्वीकार्य होता जा रहा है। 2014 का चुनाव जिन नारों पर लड़ा गया था जो वायदे उस समय किये गये थे वह 2019 के लोकसभा और इस दौरान हुये विधानसभा चुनाव में कैसे बदले गये हैं यह देश देख चुका है। एक भी मुस्लिम को टिकट न देकर भाजपा तो मुस्लिम मुक्त हो सकती है लेकिन देश नहीं। राहुल गांधी को पप्पू प्रचारित प्रसारित करने में जितना समय और संसाधन लगा दिये गये हैं उन्हीं के कारण आज मोदी का राजनीतिक कद अब हल्का पड़ता जा रहा है। महंगाई और बेरोजगारी ने हर आदमी को सरकार की कथनी और करनी को समझने के मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है। जिस तरह की राजनीतिक वस्तुस्थिति 2014 में कांग्रेस के लिए निर्मित हो गयी थी वही आज भाजपा और मोदी की होती जा रही है। विदेशों में बैठे भारतीयों को जिस मोदी ने एक समय हथियार बनाया था अब राहुल भी उसी हथियार का प्रयोग करते जा रहे हैं और इसी से सारी राजनीतिक लड़ाई स्वत:ही मोदी बनाम राहुल होती जा रही है।

डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक बचत पर 'हर घर जल' कार्यक्रम के महत्वपूर्ण प्रभाव पर प्रकाश डालती है

हम जीवन बचाने, महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने और जीवन को आसान बनाने में योगदान देने में सुरक्षित पेयजल की भूमिका देख रहे हैं: डॉ.वी के पॉल, नीति आयोग

जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2023 में प्रति सेकेंड एक पेयजल कनेक्शन प्रदान किया गया: विनी महाजन

जल जीवन मिशन में भारत सरकार के निवेश का स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ रहा है जैसा कि इस अध्ययन से पता चला है: डॉ.राजीव बहल

देश में सभी घरों के लिए सुरक्षित रूप से प्रबंधित पेयजल सुनिश्चित करने से डायरिया से होने वाली लगभग 400,000 मौतों को रोका जा सकता है

'हम जीवन बचाने, महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने और जीवन को आसान बनाने में योगदान देने में सुरक्षित पेयजल की भूमिका देख रहे हैं'। डॉ. वी के पॉल, सदस्य (स्वास्थ्य), नीति आयोग ने भारत में 'हर घर जल' कार्यक्रम के पर्याप्त लाभों पर प्रकाश डालते हुए डब्ल्यूएचओ की ग्राउंडब्रेकिंग रिपोर्ट के लॉन्च के अवसर पर यह बात कही। उन्होंने जोर देकर कहा, 'किसी भी कार्यक्रम का व्यक्तियों और परिवारों के जीवन में शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से सुधार पर इस तरह का सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है।' डॉ. पॉल ने कार्यक्रम की गति और पैमाने की सराहना की और कहा, 'हर सेकंड एक नया कनेक्शन जोड़ा जा रहा है जो आज भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य को बदल रहा है।'

रिपोर्ट का अनुमान है कि देश में सभी घरों के लिए सुरक्षित रूप से प्रबंधित

पेयजल सुनिश्चित करने से अतिसार रोगों से होने वाली लगभग 400,000 मौतों को टाला जा सकता है और इन बीमारियों से संबंधित लगभग 14 मिलियन विकलांगता समायोजित जीवन वर्ष (डीएएलवाई) को रोका जा सकता है। अकेले इस उपलब्धि से अनुमानित लागत में $101 बिलियन तक की बचत होगी। यह विश्लेषण डायरिया से होने वाली बीमारियों पर केंद्रित है क्योंकि पानी से होने वाली बीमारियां इसके लिए बड़ा कारण है।

इस मौके पर विनी महाजन, सचिव, पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, और डॉ. राजीव बहल, सचिव, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, महानिदेशक, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, डॉ. रोडेरिको एच. ओफ्रिन, डब्ल्यूएचओ के भारत के प्रतिनिधि भी मौजूद थे।

घोषणा के दौरान, डीडीडब्ल्यूएस सचिव विनी महाजन ने जल जीवन मिशन की उल्लेखनीय प्रगति पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि ग्रामीण नल जल कनेक्शन 2019 में 16.64 प्रतिशत से बढ़कर 41 महीने की अवधि के भीतर 62.84 प्रतिशत हो गए। मिशन में गति के महत्व पर बल देते हुए महाजन ने कहा कि वर्ष 2023 में अब तक प्रति सेकेंड एक पेयजल कनेक्शन प्रदान किया गया है। महाजन ने इस तथ्य पर भी प्रसन्नता व्यक्त की कि मिशन की अनुमोदित लागत 3,600 बिलियन रुपए (43,62 बिलियन अमेरिकी डॉलर) को दोगुने से भी अधिक बचाया गया है। मिशन में 100.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत वाले 13.8 मिलियन विकलांगता समायोजित जीवन वर्ष (डीएएलवाई) बचने के कारण ये संभव हो सका है।

अपने संबोधन में विनी महाजन ने कहा कि पेयजल और स्वच्छता में निवेश से आर्थिक, पर्यावरणीय, जीवन स्तर और स्वास्थ्य सहित कई परिणाम प्राप्त होते हैं। स्वच्छ पेयजल संक्रामक और गैर-संक्रामक दोनों ही रोगो से बचाव करता है। भूगर्भीय संदूषक जैसे आर्सेनिक,फ्लोराइड और भारी धातु लोगों का स्वास्थ्य कमजोर करते हैं जिससे उनकी उत्पादकता में कमी आती है। केंद्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन में किए गए निवेश से जन स्वास्थ्य पर

कई अहम प्रभाव पड़े हैं, जिसका इस अध्ययन से पता चला है।

आईसीएमआर के महानिदेशक डॉ. बहल ने नागरिकों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने में हर घर जल की उपलब्धि की सराहना की। उन्होंने कहा, 'जल जीवन मिशन में भारत सरकार के निवेश का स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण गुणक प्रभाव पड़ता है, जैसा कि इस अध्ययन से पता चला है।'

'हर घर जल' रिपोर्ट डायरिया संबंधी बीमारियों पर ध्यान केंद्रित करती है क्योंकि वे पानी, सफाई और स्वच्छता (वॉश) मुद्दों से संबंधित समग्र रोग के बोझ में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। विश्लेषण इन बीमारियों को दूर करने की तत्काल आवश्यकता और सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक कल्याण में पर्याप्त लाभ की संभावना को रेखांकित करता है।

2019 से पहले ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति की स्थिति चुनौतीपूर्ण थी। रिपोर्ट से पता चलता है कि 2018 में, भारत की कुल आबादी का 36 प्रतिशत, जिसमें 44 प्रतिशत ग्रामीण आबादी शामिल है, के पास अपने परिसर में बेहतर पेयजल स्रोतों तक पहुंच नही थी। असुरक्षित पेयजल के प्रत्यक्ष उपयोग के गंभीर स्वास्थ्य और सामाजिक परिणाम हुए। विश्लेषण इंगित करता है कि 2019 में, असुरक्षित पेयजल, अपर्याप्त सफाई और स्वच्छता के साथ, वैश्विक स्तर पर 1.4 मिलियन मौतों और 74 मिलियन डीएएलवाई में योगदान दिया।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) विभिन्न सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) संकेतकों की निगरानी करता है, जिसमें सुरक्षित रूप से प्रबंधित पेयजल सेवाओं (संकेतक 6.1.1) और असुरक्षित पानी, सफाई और स्वच्छता से संबंधित मृत्यु दर (संकेतक 3.9.2) का उपयोग करने वाली आबादी का अनुपात शामिल है। डब्ल्यूएचओ ने पानी, सफाई और स्वच्छता में सुधार से जुड़े स्वास्थ्य लाभों का अनुमान लगाने के लिए तरीके और उपकरण विकसित किए हैं, विशेष रूप से डायरिया संबंधी बीमारियों और अन्य संबंधित स्वास्थ्य परिणामों को कम करने में।

रिपोर्ट नल के पानी के प्रावधान के माध्यम से महिलाओं और लड़कियों के लिए बचाए गए जबरदस्त समय और प्रयास पर जोर देती है। 2018 में, भारत में महिलाओं ने घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए रोजाना औसतन 45.5 मिनट पानी इकट्ठा करने में खर्च किया। कुल मिलाकर, जिन घरों में ऑन-प्रिमाइसेस पानी नही है, वे हर दिन पानी इकट्ठा करने में चौंका देने वाले 66.6 मिलियन घंटे खर्च करते हैं, जिनमें से अधिकांश (55.8 मिलियन घंटे) ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं। नल के पानी के प्रावधान के माध्यम से सार्वभौमिक कवरेज के परिणामस्वरूप दैनिक जल संग्रह प्रयासों की आवश्यकता को समाप्त करके पर्याप्त बचत होगी।

घोषणा के दौरान डीडीडब्ल्यूएस सचिव विनी महाजन ने जन जीवन मिशन की उल्लेखनीय प्रगति पर प्रकाश डाला। उन्होने बताया कि ग्रामीण नल जल कनेक्शन 2019 में 16.64 प्रतिशत से बढ़कर केवल 41 महीने की अवधि में 62.84 प्रतिशत हो गए। इसमें केवल 0.23 प्रतिशत प्रति वर्ष के मुकाबले में वार्षिक आधार पर औसतन 13.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

'हर घर जल' कार्यक्रम के बारे में:

जल शक्ति मंत्रालय के तहत जल जीवन मिशन द्वारा कार्यान्वित हर घर जल कार्यक्रम की घोषणा 15 अगस्त, 2019 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा की गयी थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पर्याप्त आपूर्त के लिए नलों के माध्यम से सुरक्षित पेयजल तक सस्ती और नियमित पहुंच प्रदान करना है। सुरक्षित रूप से प्रबंधित पेयजल सेवाओं के लिए एसडीजी 6.1 पर प्रगति की निगरानी के लिए कार्यक्रम के घटक जल आपूर्ति, सफाई और स्वच्छता के लिए डबल्यूएचओ /यूनिसेफ के संयुक्त निगरानी कार्यक्रम के साथ संरेखित हैं।

अमरनाथ यात्रा स्वच्छ तीर्थ की ओर अग्रसर

स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत यात्रियों के लिए एक स्वच्छ और अपशिष्ट मुक्त माहौल सुनिश्चित करने के लिए कई पहल की जा रही हैं। साफ-सफाई की सुविधाओं और स्वच्छता तथा एक जिम्मेदार अपशिष्ट निपटान के साथ-साथ मजबूत अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियां लागू की जा रही हैं। इन उपायों से अमरनाथ यात्रा के स्वच्छता मानकों में काफी बढौतरी हुई है। इससे यह यात्रा पर्यावरण के प्रति जागरूक तीर्थयात्रा के रूप में परिवर्तित हो रही है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जुलाई और अगस्त के बीच दक्षिण कश्मीर में अमरनाथ की पवित्र गुफा के दर्शन के लिए हर साल बड़ी संख्या में भक्तगण यहां पहुंचते हैं, जिसके कारण भारी मात्रा में कचरा भी पैदा होता है। इस प्रसिद्ध तीर्थ स्थल की पवित्रता बनाए रखने के लिए एक प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन रणनीतियों की आवश्यकता महसूस होती है।

वर्ष 2022 में अमरनाथ यात्रा के दौरान शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) ने बेहतर साफ-सफाई के लिए यात्रा मार्ग में कुल 127 शौचालय, 119 पेशाबघर और 40 स्नानघर स्थापित किए थे और उनका रखरखाव भी किया था। इसके अलावा यूएलबी ने इस यात्रा के दौरान 780 से अधिक अन्य शौचालयों का भी रखरखाव किया था। शत-प्रतिशत कचरा संग्रह करने के लिए यूएलबी ने दैनिक आधार पर 10 जुड़वां डिब्बों वाले वाहनों का भी उपयोग किया था। ऐसे 145 जुड़वां डिब्बे कचरा अलग-अलग करने की सुविधा के लिए सभी शिविरों में स्थापित किए थे। सैनिटरी कचरे के निपटान के लिए महिला शौचालय के बाहर निर्दिष्ट काले कूड़ेदान रखे गए थे। पिछले वर्ष यात्रा के दौरान लगभग 150 मीट्रिक टन गीला कचरा, 130 मीट्रिक टन सूखा कचरा और 10-12 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न हुआ था। इस पैदा हुए कचरे के निपटान के लिए यूएलबी ने यात्रा के दौरान प्रतिदिन 14 'डी-स्लजिग' वाहनों को आपात स्थिति में उपयोग के लिए अतिरिक्त वाहनों के साथ तैनात किया था। यूएलबी द्वारा कुल 2596 किलो लीटर सेप्टेज को हटाकर उसका सफलतापूर्वक निपटान किया गया था।

साफ-सफाई और स्वच्छता बनाए रखने के लिए यूएलबी ने आवास क्षेत्रों और उनके आसपास की सड़कों तथा अन्य प्रतिष्ठानों में 231 सफाई कर्मचारियों को तैनात किया था। इन कामगारों को उपयुक्त यूनिफार्म, पीपीई किट, दस्ताने, गम बूट, मास्क और झाड़ू आदि उपलब्ध कराये गए थे।

टडूलिप (द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम) कार्यक्रम के हिस्से के रूप में अनेक स्वच्छ-ग्राहियों को यात्रा के दौरान आवास क्षेत्रों में तैनात किया गया था। उन्होंने पूरी साफ-सफाई और स्वच्छता की निगरानी की और ठोस अपशिष्ट संग्रह तथा पृथक्करण में मदद की। एसयूपी के उपयोग न करने की अपील की और स्वच्छता का संदेश भी फैलाया। शौचालयों, लंगरों/भण्डारों में क्यूआर कोड के माध्यम से टयूलिप के कर्मियों ने यात्रियों से स्वच्छता के बारे में फीडबैक भी लिया। यात्रियों के लिए विशेष सेल्फी पॉइंट भी स्थापित किए गए थे। अमरनाथ यात्रा के एक हिस्से के रूप में यात्रियों के अनुभव को बढ़ाने के लिए कई विशिष्ट गतिविधियां भी शुरु की गई थी।

कुशल कचरा प्रसंस्करण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जम्मू और कश्मीर में स्थित 10 यूएलबी में 12 मई, 2023 को 9 ठोस कचरा प्रबंधन सुविधाओं का उद्घाटन किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि इनमें से तीन यूएलबी- काजीगुंड, सुंबल और गांदरबल यात्रा मार्ग के अंतर्गत आती हैं। इन सेवाओं से 40 टन से अधिक कचरे की रोजाना प्रोसेसिंग की जाएगी। प्रत्येक केंद्र में सूखे कचरे के लिए सामग्री रिकवरी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, जिनमें पृथक्करण, बेलिंग और श्रेडिंग सुविधाएं भी शामिल हैं। गीले कचरे के प्रसंस्करण के लिए कम्पोस्ट खाद के गड्डे भी उपलब्ध कराए गए हैं। वर्ष 2023 की अमरनाथ यात्रा की तैयारियों में कुछ अतिरिक्त उपाय किए गए हैं, जिनमें अधिक पूर्वनिर्मित शौचालयों का अधिग्रहण, उपकरण और संयंत्रों की खरीद, कीटानाशकों की खरीद, अतिरिक्त स्वच्छता कर्मचारियों को काम पर रखना, अधिक स्वच्छग्राहियों को साफ-सफाई कार्य में शामिल करना, आवास क्षेत्रों और यात्रा मार्ग में यात्रों से पूर्व साफ-सफाई करना, सेप्टिक टैंकों की साफ-सफाई, स्वच्छता दलों का गठन, नोडल अधिकारियों की नियुक्ति और अन्य पहलें शामिल हैं। स्वच्छ अमरनाथ यात्रा के माध्यम से, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 ने न केवल तीर्थ यात्रियों के समग्र अनुभवों को बेहतर बनाया है, बल्कि उनमें स्वच्छता और साफ-सफाई के मूल्यों को भी मजबूत बनाया है।

रोबोटिक सर्जरी आधुनिक स्वास्थ्य सेवा की दिशा में महत्वपूर्ण कदमः मुख्यमंत्री

सरकार द्वारा टांडा मेडिकल कॉलेज में दो रोबोटिक कैथलैब को स्वीकृति

शिमला। राज्य सरकार ने जिला कांगड़ा के टांडा स्थित डॉ. राजेन्द्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में दो रोबोटिक कैथलैब स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की है। इस संबंध में कॉलेज प्रशासन को विस्तृत प्रस्ताव देने को कहा गया है। रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत कर राज्य में आधुनिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की दिशा में यह पहला कदम है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में आधुनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला और सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल चमियाना में भी रोबोटिक सर्जरी सुविधाएं शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को इन संस्थानों से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्राप्त हुई है, जिसकी विशेषज्ञों द्वारा जांच की जा रही है। इस उद्देश्य के लिए सैद्धांतिक रूप से 30 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और राज्य सरकार इसके लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा प्रक्रियाओं के संचालन में रोबोटिक कैथलैब क्रांति ला सकती है। रोबोटिक्स तकनीक का उपयोग सर्जरी के दौरान सटीकता, बेहतर दृष्टि और अधिक नियंत्रण प्रदान कर सकता है। इससे सर्जरी के दौरान जटिलताओं में कमी आएगी और रोगी शीघ्र स्वस्थ होंगे।

उन्होंने कहा कि कैथलैब एक विशेष चिकित्सा सुविधा है, जो मुख्य रूप से काडियोलॉजी (हृदय रोग विज्ञान) के क्षेत्र में मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी के लिए इमेजिंग तकनीक का उपयोग करती है। कैथलैब में रोबोटिक तकनीक को शामिल कर सर्जरी के दौरान सटीकता और दक्षता में काफी वृद्धि की जा सकती है, जो रोगियों, चिकित्सकों और चिकित्सा कर्मियों के लिए फायदेमंद होगी।

राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए सरकार आधुनिक चिकित्सा तकनीक में निवेश करने की योजना बना रही है, जो दो उद्देश्यों की पूर्ति करेगी। प्रथम उद्देश्य के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि राज्य के लोगों को सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में नवीनतम चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हों। दूसरे उद्देश्य के अंतर्गत राज्य में चिकित्सा उपचार के इच्छुक आगंतुकों को आकर्षित करने के लिए स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करते हुए राजस्व भी उत्पन्न करेगी।

ऐसे भी चुकाया जा सकता मातृ ऋण

पितृ ऋण, देव ऋण और गुरु ऋण की धारणाएं भारतीय संस्कृति के वह मूल्य हैं जिन पर जितना मनन -चिन्तन किया जाये उनका अर्थ उतना ही गहराता चला जाता है। इन्हीं मूल्यों के आधार पर किसी संस्कृति का आकलन और उसकी उपादेयता स्थापित की जा सकती है। जो समाज अपने को इन मूल्यों से जितना जोड़े रखेगा वह उतना ही जीवन्त बन जायेगा। आज का समाज जिस बिखराव की ओर बढ़ता जा रहा है उससे आने वाले समय में इतनी समस्याएं खड़ी हो जायेगी जिनका समाधान किसी भी सरकार के लिये एक बड़ी समस्या बन जायेगा। क्योंकि अब व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अवधारणा और अराजकता में कोई बड़ा अन्तर नहीं रह गया है। जन्म देने वाले माता-पिता जब बच्चों की जिम्मेदारी न रहकर समाज और सरकार की समस्या बन जाये तो अन्दाजा लगाया जा सकता है कि क्या होने वाला है। ऐसे समाज को किन्ही प्रवचनों से सुधारने की संभावना जब लगातार क्षीण होती जाये तब व्यक्तिगत आचरण ही एकमात्र उपाय और उम्मीद रह जाती है। ऐसे समय में कृष्ण कुमार जैसे लोग ही उम्मीद की अन्तिम किरण नजर आते हैं। मैसूर निवासी कृष्ण कुमार जिस तरह से अपनी माता श्री को स्कूटर पर भारत भ्रमण और देव दर्शन करवाने निकले हैं उन्हें देख कर स्वत: ही नमन करने का मन हो जाता है। अब तक 70555 किलोमीटर स्कूटर से यात्रा कर शिमला पहुंचे कृष्ण कुमार को मन की गहराइयों से साधुवाद कहते हुये शैल समाचार परिवार उनकी यात्रा की सफलता की कामना करता है।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश हितों के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से सहयोग मांगा

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह के हाल ही में किन्नौर जिला के दौरे के दौरान प्रदेश हित में ऊर्जा क्षेत्र से सम्बधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और उनसे सहयोग करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री के ध्यानार्थ प्रस्तुत किया कि केन्द्रीय संयुद्र उपक्रम सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एस.जे.वी.एन. एल.) व भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बी. बी.एम.बी.) के अधीन बनाई गयी कई परियोजनाएं ऋण मुक्त हो चुकी हैं, जिनमें नाथपा झाकड़ी, रामपुर, भाखड़ा बांध, ब्यास सतलुज लिंक व पौंग बांध परियोजनाएं शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री के संज्ञान में लाया कि वर्तमान में एस. जे.वी.एन.एल. द्वारा संचालित नाथपा झाकड़ी परियोजना (1500 मैगावाट) व रामपुर परियोजना (412 मेगावाट) से प्रदेश को केवल 12 प्रतिशत की दर पर मुफ्त बिजली प्राप्त हो रही है जबकि एस.जे.वी.एन.एल. को इन ऋण मुक्त हो चुकी परियोजनाओं से लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं में अनुबन्ध अवधि सीमा भी निर्धारित नही की गयी है। यह प्रदेश हित में होगा कि इन परियोजनाओं में अन्य परियोजनाओं की भान्ति 40 वर्ष की समय अवधि निर्धारित करने के साथ-साथ मुफ्त बिजली की दरों में बढ़ौतरी की जाये।

मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री के समक्ष एस.जे.वी.एन.एल. द्वारा कार्यन्वयन अनुबंध हस्ताक्षरित किए बिना ही लुहरी चरण-1 (210 मैगावाट), धौलासिद्ध (66 मैगावाट) व सुन्नी बांध (382 मैगावाट) का निर्माण कार्य शुरू करने का मामला भी उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा बार-बार अनुरोध करने के बाद भी एस.जे.वी.एन.एल. द्वारा अनुबंध हस्ताक्षरित नहीं किया जा रहा है तथा ऊर्जा नीति में वर्णित प्रावधानों को मानने में भी आनाकानी की जा रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी अवगत करवाया कि प्रदेश सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है।

इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि बी.बी.एम.बी. द्वारा संचालित भाखड़ा बांध परियोजना (1478 मैगावाट), ब्यास सतलुज लिंक(990 मैगावाट) व पौंग बांध परियोजना (396 मैगावाट) में किसी प्रकार की मुफ्त बिजली की रॉयल्टी नहीं दी जा रही है। इसके कारण प्रदेश सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व से वंचित होना पड़ रहा है। हालांकि केन्द्रीय व राज्य सरकार द्वारा पारित ऊर्जा नीतियों में सभी परियोजनाओं से प्रदेश सरकार को मुफ्त बिजली रॉयल्टी के रूप में देने का प्रावधान किया गया है। जबकि बी.बी. एम.बी. द्वारा इन परियोजनाओं से प्रदेश सरकार को हिस्सेदारी के रूप में केवल मात्र 7.19 प्रतिशत बिजली निर्धारित दरों पर प्रदान की जा रही है, जो पर्याप्त नही है। इन परियोजनाओं में उपयोग की गयी भूमि व जल सम्पदा का सम्पूर्ण स्वामित्व हिमाचल प्रदेश का है और इसके लिए कई परिवारों को विस्थापित होना पड़ा। अत: इन परियोजनाओं में भी अन्य परियोजनाओं की भान्ति मुफ्त बिजली रॉयल्टी के रूप में दी जानी न्यायसंगत होगा।

केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के.सिंह ने मुख्यमंत्री द्वारा उठाये गये मुद्दों पर गंभीरतापूर्ण विचार कर उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री ने लम्बित परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृतियां प्रदान करने का आश्वासन दिया

निवेशकों की सुविधा के लिए निवेश नीति में संशोधन करेगी प्रदेश सरकार

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य स्तरीय गोष्ठी (फोरम) के दूसरे चरण के दौरान प्रदेश में 7828 करोड़ रुपए की 26 लम्बित परियोजनाओं

की कार्यान्वयन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए पर्यटन, जल विद्युत तथा औद्योगिक क्षेत्रों के हितधारकों के साथ चर्चा की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रत्येक परियोजना का स्वयं जायजा लिया तथा इनके विलम्ब के कारणों की जानकारी प्राप्त की।

मुख्यमंत्री ने इस गोष्ठी के प्रथम चरण में 8468 करोड़ रुपए की 29 लम्बित परियोनाओं के लिए निवेशकों से चर्चा की थी। प्रदेश में अटकी पड़ी 16297 करोड़ रुपए की कुल 55 परियोजनाओं से 20 हजार से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

उद्योग स्थापित करने में विलम्ब पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने निवेशकों को आश्वस्त किया कि प्रदेश सरकार राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए हरसम्भव प्रयास कर रही है तथा परियोजनाओं की स्थापना में आने वाली अड़चनों को दूर करने पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निवेशकों को सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर काटने से बचाने के लिए सरकार निवेश नीति में संशोधन कर रही है। उन्होंने निवेशकों को बेझिझक अपनी समस्याएं प्रदेश सरकार के साथ साझा करने का आग्रह किया तथा इनके समाधान का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि सरकार निवेश को नयी दिशा देने पर विशेष बल दे रही है जिसमें जल विद्युत, पर्यटन तथा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र भी शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पर्यटन विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है तथा कांगड़ा जिला प्रदेश की पर्यटन राजधानी बनेगी। उन्होंने कहा कि सरकार स्वयं पर्यटन क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश करेगी। कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार तथा सभी ज़िला मुख्यालयों में हेलीपोर्ट का निर्माण चरणबद्ध ढंग से किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सरकार प्रदेश में चिकित्सा उपचार के इच्छुक आगंतुकों को आकर्षित करने के लिए स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा दे रही है।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य से बाहर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कार्य कर रहे प्रदेश के युवाओं के लिए राज्य में ही रोजगार व स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने तथा राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। ज़िला कांगड़ा के पालमपुर में सूचना प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने के लिए भूमि चिन्हित की गयी है।

प्रदेश की आर्थिकी में जल विद्युत क्षेत्र के महत्वपूर्ण योगदान को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने राज्य की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए जल उपकर अधिनियम पारित किया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में ऊर्जा परियोजनाओं के निर्माताओं की सुविधा के लिए खुली जल विद्युत नीति लाने पर कार्य किया जा रहा है। सरकार जल विद्युत परियोजनाओं को आर्थिक रूप से सफल बनाने तथा उनके निर्माण में आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए हरसम्भव सहयोग प्रदान करेगी।

इसके उपरांत ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में निवेश करने के इच्छुक उद्यमियों के साथ पारस्परिक चर्चा की तथा उनकी परियोजना को शीघ्र स्थापित करने के लिए उनके विचार सुने।

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। निवेश से न केवल युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे बल्कि प्रदेश को राजस्व भी प्राप्त होगा। उन्होंने संभावित उद्यमियों की बैठकें आयोजित करने के लिए मुख्यमंत्री के प्रयासों की सराहना की और आशा व्यक्त की कि यह अनूठा कदम परियोजनाओं को धरातल पर उतारने में मील का पत्थर साबित होगा।

प्रधान सचिव पर्यटन देवेश कुमार ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और प्रदेश में राजस्व वृद्धि के लिए पर्यटन क्षेत्र की संभावनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

बैठक में हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष रघुबीर सिंह बाली, मुख्य संसदीय सचिव राम कुमार चौधरी, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, निदेशक उद्योग यूनुस, निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क किरण बड़ाना, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और सम्भावित निवेशक भी शामिल हुए।

प्रदेश सरकार ने पथ परिवहन निगम के निदेशक मंडल का किया पुनर्गठन

राज्य परिवहन प्राधिकरण का भी सरकार ने किया गठन
पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों की 4.5 करोड़ की देनदारी जारी

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार की ओर से प्रदेश पथ परिवहन निगम के निदेशक मंडल का पुनर्गठन किया है। इस संबंध में परिवहन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गयी है। निदेशक मंडल में उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के अलावा, प्रधान सचिव परिवहन, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, प्रधान सचिव वित्त, केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के संयुक्त सचिव, पथ परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक और निदेशक परिवहन शामिल होंगे।

इसके अलावा गैर सरकारी सदस्य के तौर पर रणजीत राणा, रामगोपाल शर्मा, मोहिन्द्र संधु, धर्मेंद्र धामी, प्रताप सूर्या, विवेक सिंह राणा, निशांत ठाकुर, सुरजीत कुमार भरमौरी, मनमोहन कटोच, चतर सिंह ठाकुर निदेशक मंडल में शामिल किए गए हैं।

प्रदेश सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार सरकार ने राज्य परिवहन प्राधिकरण का भी गठन किया है। प्रधान सचिव परिवहन इसके अध्यक्ष होंगे। निदेशक परिवहन इसके सदस्य एवं सचिव राज्य परिवहन प्राधिकरण इसके सदस्य सचिव होंगे। प्राधिकरण में गैर सरकारी सदस्यों को भी नामित किया है। इसमें अशोक ठाकुर, अंजना धीमान, बलदेव ठाकुर और सुनील दत्त शर्मा को शामिल किया गया है।

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि परिवहन विभाग प्रदेश के लोगों के लिए बेहतर परिवहन सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार द्वारा गठित पथ परिवहन निगम का निदेशक मंडल और राज्य परिवहन प्राधिकरण जन कल्याणकारी नीतियां एवं योजनाएं बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस वर्ष ग्रीन बजट पेश किया है। इसके तहत सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में सरकार द्वारा 20 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदी गयी हैं। इन बसों को एक सप्ताह के भीतर मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।

उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों और पैन्शनरों की देनदारी के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि निगम के कर्मचारियों की विभिन्न देनदारियों के लिए 4.5 करोड़ रुपए की राशि जारी की गयी है। इसके तहत दिसम्बर 2022 का 2.85 करोड़ राशि का ओवर टाइम भत्ता और रात्रि भत्ता शामिल है। इसी तरह जनवरी 2023 का रात्रि भत्ता भी जारी कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि फरवरी 2023 के रात्रि भत्ते और ओवर टाइम भत्ते के तहत 2.50 करोड़ रुपए की राशि सरकार द्वारा पहले ही जारी कर दी गयी है। इसके अलावा फरवरी 2019 का 2.8 करोड़ रुपए का रात्रि भत्ता और ओवर टाइम भत्ता भी कर्मचारियों को प्रदान किया गया है।

उन्होंने कहा कि निगम के जनवरी 2023 तक सेवानिवृत कर्मचारियों के पीपीओ नंबर जारी किए जा चुके हैं। इसके अलावा पैन्शनरों की सितम्बर 2022 तक लीव-इन-कैशमेंट और ग्रेच्युटी से संबंधित सारी देनदारी पथ परिवहन निगम द्वारा जारी कर दी गयी है।

पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए पर्याप्त राशि व स्टाफ सुनिश्चित किया जाएगा:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पुलिस विभाग में सुधार पर बल देते हुए कहा कि विभाग के आधुनिकीकरण के लिए पर्याप्त निधि तथा पुलिस बल के सुचारू

व प्रभावी कार्यान्वयन के लिए स्टाफ में वृद्धि की जाएगी। राज्य सरकार प्रदेश में सरकारी भवनों के निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भी सार्थक प्रयास कर रही है।

मुख्यमंत्री ने ओक ओवर से वर्चुअल माध्यम से सोलन में पुलिस विभाग के आवासीय भवन का उद्घाटन करने के उपरांत पुलिस विभाग द्वारा प्रकाशित कॉफी टेबल बुक 'एक्सपीरियंस दी वॉटर्स आफ हिमाचल' भी जारी की। प्रदेश में इस वर्ष जिला ऊना के अंदरोली में आयोजित 22वीं अखिल भारतीय पुलिस जल क्रीड़ा प्रतियोगिता की झलकियां इसमें प्रस्तुत की गयी हैं। इसके अतिरिक्त इसमें प्रदेश के मनमोहक जलाशयों को भी प्रदर्शित किया गया है। मुख्यमंत्री ने विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इससे राज्य में जल क्रीड़ा को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ.(कर्नल) धनी राम शांडिल तथा मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर कुल्लू से वर्चुअली इसमें शामिल हुए।

पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और पुलिस विभाग द्वारा की जा रही विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी।

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष रघुबीर सिंह बाली, विधायक हरीश जनारथा और विनोद सुल्तानपुरी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सतर्कता) सतवंत अटवाल, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) अभिषेक त्रिवेदी तथा पुलिस विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

रोप-वे परियोजना से 'पहाड़ों की रानी' की बदलेगी तस्वीर:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। पहाड़ों की रानी शिमला को यातायात जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए प्रदेश सरकार रोप-वे परियोजना पर कार्य कर रही है। इसके माध्यम से पर्यावरण मित्र, साफ-सुथरा एवं हरित परिवहन सेवाओं पर कार्य करके शहर की पर्यटन क्षमता को भी प्रोत्साहित किया जा सकेगा।

पहाड़ी इलाकों और दूरदराज के क्षेत्रों में एक कुशल परिवहन नेटवर्क विकसित करना एक बड़ी चुनौती है। परिवहन के पारंपरिक साधनों जैसे सड़क, रेल और वायु मार्ग का उपयोग करके ऐसे क्षेत्रों में सुदृढ़ परिवहन नेटवर्क स्थापित करने के लिए कई तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसी के दृष्टिगत मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सोच है कि प्रदेश में परिवहन के सुरक्षित, अभिनव और किफायती तरीकों के उपयोग के माध्यम से ऐसे स्थानों को वाहनों की भीड़-भाड़ से मुक्त किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला रोपवे परियोजना का विस्तार 14.13 किलोमीटर का होगा और यह शहर के विभिन्न स्थानों पर 15 स्टेशनों को आपस में जोड़ेगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की कुल परियोजना लागत लगभग 1546.40 करोड़ रुपये है। यह शहरी रोपवे परियोजना दुनिया में अपनी तरह की दूसरी और भारत में पहली होगी और इससे शिमला शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार धर्मशाला और मनाली शहर में इसी तरह की शहरी रोप-वे परियोजनाओं को विकसित करने की योजना बना रही है।

शिमला शहर के लिए यह परियोजना रोप-वे एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के माध्यम से संचालित की जाएगी और निगम ने इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी में पर्याप्त प्रगति की है, जिसके 30 जून 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है। इसके लिए ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। इसके अलावा, भू-तकनीकी जांच और ईएसआईए की अध्ययन प्रक्रिया जारी है।

मुख्यमंत्री का कहना है कि रज्जू मार्ग (रोप-वे) परिवहन के एक सुविधाजनक, सुरक्षित और पसंदीदा साधन के रूप में उभरा है, जो हिमाचल जैसे पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में तीव्र सम्पर्क सुविधा प्रदान करने के साथ-साथ शहरों को भीड़-भाड़ से भी राहत प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण के अनुकूल, स्वच्छ और हरित परिवहन साधन होने के अलावा यह हरित और स्वच्छ हिमाचल के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को साकार करने में मदद करेगा।

शिमला की जनसंख्या लगभग 3.08 लाख है और यहां वार्षिक लगभग 40 लाख पर्यटक पहुंचते हैं। शहर के दोनों तरफ बसावट के साथ संकरी सड़कें हैं, जो पर्यटन सीजन के दौरान शिमला पहुंचने वाले हजारों पर्यटक वाहनों के साथ और भी जटिल हो जाती हैं, जिससे यात्रियों को यातायात जाम से भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। रोप-वे परियोजना शिमला के प्रवेश बिंदु पर यहां आने वाले पर्यटकों को अपने वाहनों को पार्क करने के उपरांत शिमला की मनोहारी पहाड़ियों की प्राकृतिक सुंदरता और यहां के शांत वातावरण का आनंद लेने के लिए दूरगामी सिद्ध होगा।

केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और मुख्यमंत्री ने सीमा क्षेत्रों में विकास कार्यों की समीक्षा की

शिमला/शैल। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सेना और

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस 17वीं आईटीबीपी बटालियन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जिला किन्नौर के रिकांगपिओ में बैठक की अध्यक्षता की।

इस अवसर पर सेना और आईटीबीपी के अधिकारियों ने केंद्रीय मंत्री एवं मुख्यमंत्री को उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित प्रस्तुति दी।

उपायुक्त, किन्नौर, तोरुल एस. रवीश ने जिला किन्नौर और लाहौल-स्पीति में सरकार द्वारा चलाये जा रहे वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम पर विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने दोनों जिलों में विभिन्न अवसरों और चुनौतियों से भी अवगत भी करवाया।

बैठक में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा, सेना और आईटीबीपी और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और मुख्यमंत्री ने 450 मेगावाट की शांगटांग कड़छम हाइड्रो विद्युत परियोजना में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की।

इसके पश्चात, स्थानीय ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों ने कल्पा विश्राम गृह में केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया।

सेब सीजन में सड़कों का उचित रखरखाव सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता:विक्रमादित्य सिंह

शिमला/शैल। आगामी सेब सीजन के दृष्टिगत सड़कों के रखरखाव एवं अन्य कार्यों की समीक्षा के लिए लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया।

लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि हिमाचल फल उत्पादक प्रदेश के रूप में विख्यात है और बागवानी विशेषतौर पर सेब उत्पादन से राज्य में लगभग

5 हजार करोड़ रुपए की आर्थिकी जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि ऐसे में यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि सेब, नाशपाती तथा प्लम इत्यादि की फसल समय पर मण्डियों तथा वहां से आगे बाजार तक पहुंचाई जाये। इसके लिए प्रदेश सरकार और लोक निर्माण विभाग समय रहते सभी तैयारियां पूर्ण करने के लिए कृतसंकल्प है। इसी कड़ी में सेब सीजन के दृष्टिगत यह बैठक आयोजित की गई है।

बैठक में सेब सीजन के लिए प्रशासनिक स्तर पर विभिन्न तैयारियों तथा सड़कों के बेहतर रखरखाव के लिए आपसी समन्वय से कार्य करने पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि शिमला जोन में पांच वृत्तों की 14 सड़कों की त्वरित मरम्मत एवं रखरखाव पर लगभग साढ़े तीन करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि व्यय की जाएगी, ताकि आढ़ती, लदानी, किसान एवं बागवानों को आगामी सेब सीजन में अपनी फसल की ढुलाई में किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

लोक निर्माण मंत्री ने पराला, रोहडू, भट्टाकुफर, सोलन और परवाणु स्थित एपीएमसी मार्किट यार्ड को जोड़ने वाली सड़कों के उचित रखरखाव के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पराला मार्किट यार्ड की सड़क के लिए एपीएमसी के माध्यम से लगभग 3.48 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। इसके अतिरिक्त डिपोजिट वर्क में भी एपीएमसी से राशि का मामला उठाया गया है ताकि छिटपुट मरम्मत कार्य समय पर पूर्ण किए जा सकें।

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि बरसात के मौसम में भूस्खलन इत्यादि की स्थिति में सड़क यातायात बहाल रखने के लिए प्रत्येक मण्डल में मशीनों इत्यादि की समुचित व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर की सम्पर्क सड़कों के रखरखाव के लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के समन्वय से खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से सहयोग लिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी करते हुए कहा कि सेब सीजन के लिए अभी लगभग एक माह का समय शेष है और इस अवधि में वे सभी तैयारियां पूर्ण कर लें। सीजन के दौरान सड़कों के रखरखाव में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सेब सीजन शुरू होने से पूर्व जुलाई माह में वे एक बार पुन: इसकी समीक्षा करेंगे।

उन्होंने कहा कि सेब उत्पादन क्षेत्र में आने वाली सड़कों में ब्लैक स्पॉट, तीखे एवं संकरे मोड़ तथा दुर्घटना सम्भावित क्षेत्रों में समुचित चेतावनी चिन्ह भी प्रदर्शित किए जाएंगे। इसमें पुलिस विभाग से भी समन्वय स्थापित कर आवश्यक सहयोग लिया जाएगा।

बैठक में सेब उत्पादन से जुड़े शिमला, कुल्लू और किन्नौर ज़िलों की प्रमुख सड़कों, पंचायत एवं ग्राम स्तर की सम्पर्क सड़कों, शिमला व ठियोग बाईपास को खुला रखने तथा छैला सड़क मार्ग विस्तारीकरण की अद्यतन स्थिति पर चर्चा की गयी। इसके अतिरिक्त ठियोग सहित विभिन्न स्थानों पर नियंत्रण एवं उप-नियंत्रण कक्ष स्थापित करने पर भी चर्चा की गई।

बैठक में सचिव वित्त अक्षय सूद, उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी, पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी, लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता सुरेंद्र कुमार जगोता, विभाग के अधीक्षण एवं अधिशाषी अभियंता तथा बागवानी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

रबी फसलों की मूल्य नीति, विपणन मौसम 2024-25 के संबंध में बैठक आयोजित

शिमला/शैल। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के अध्यक्ष प्रो. विजय पॉल शर्मा ने हिमाचल प्रदेश के कृषि विभाग के तत्वावधान में उत्तरी राज्यों के लिए रबी फसलों की मूल्य नीति 2024-25 के संबंध में आयोजित बैठक की

अध्यक्षता की।

उन्होंने कहा कि आयोग का मुख्य उद्देश्य कृषक समुदाय को आधुनिक तकनीक को अपनाने, उत्पादकता को बढ़ावा तथा देश में समग्र अनाजों को बढ़ावा देना है। आयोग विभिन्न वस्तुओं की मूल्य नीति की सिफारिश करते समय मूल्य और आपूर्ति, उत्पादन की लागत, बाज़ार में घरेलू और अन्तरराष्ट्रीय कीमतों के उछाल और अंतर फसल मूल्य समता जैसे विभिन्न घटकों का विश्लेषण करता है। इसके अतिरिक्त कृषि और गैर कृषि व्यापार की शर्तें, उत्पादन लागत पर मार्जन के रूप में 50 प्रतिशत और उपभोक्ताओं पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के प्रभावों का भी विश्लेषण करता है।

उन्होंने कहा कि किसानों को नवीनतम तकनीक और पद्धति को अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। खेती की लागत कम करने की दिशा में भी उन्हें जागरूक किया जा रहा है।

इस अवसर पर कृषि सचिव राकेश कंवर ने सभी गणमान्यों का स्वागत करते हुए कहा कि किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने की दिशा में इस प्रकार की क्षेत्रीय बैठकें महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। राज्य सरकार प्रदेश के किसानों के उत्पादों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार किसानों की आय को बढ़ाने की दिशा में किसान हितैषी नीतियां बना रही है। प्रदेश में एकीकृत एवं समग्र कृषि गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य में किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने की दिशा में और उनके उत्पादों के विपणन के लिए अभिनव प्रयास किए जा रहे हैं।

बैठक में 23 कृषि उत्पादों, जिसमें 7 अनाज (धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ और रागी,) पांच दालें चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर, सात तिलहन (मूंगफली, रेपसीड-सरसों, सोयाबीन, तिल, सूरजमुखी, कुसुम, नाइजर सीड) और चार वाणिज्यिक फसलों (कोपरा, गन्ना, कपास और कच्चा जूट) आदि का न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि संबंधित अन्य मुद्दों पर चर्चा की गयी।

बैठक में कृषि लागत और मूल्य आयोग (सी.ए.पी.सी) के सदस्य डॉ. नवीन सिंह, रतन लाल डग्गा, अनुपम मित्रा और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखण्ड तथा हिमाचल प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय के हितधारक विशेष रूप से उपस्थित रहे।

बैठक में निदेशक कृषि डॉ. राजेश कौशिक ने धन्यावाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

इस अवसर पर निदेशक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति आर.के.गौतम, पुरस्कृत किसानों, कृषि एवं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया।

देश के सबसे लंबे रूट पर बस सेवा शुरु

शिमला/शैल। देश के सबसे लंबे और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रों से गुजरने वाली हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की रोमांचकारी दिल्ली-लेह बस सेवा शुरु हो गयी है।

ये रूट बारालाचा दर्रा (4850 मी.), तांगलंग दर्रा (5328 मी.) व नाकी दर्रा (4769 मी.) से होकर मनोहारी स्थानों सरचू, पांग आदि से गुजरता है, जिसकी कुल लम्बाई 1026 किलोमीटर है तथा कुल किराया 1736 रुपए होगा। इस रूट पर तीन चालक और दो परिचालक सेवाएं देंगे।

बस दोपहर बाद 3.45 बजे दिल्ली से चलेगी और अगले दिन सुबह 10.30 पर केलांग पहुंचेगी। रात्रि ठहराव केलांग में रहेगा। सुबह 5.30 बजे बस केलांग से लेह के लिए रवाना होगी तथा अगले दिन प्रात: 4 बजे बस लेह पहुंचेगी। बस का सफर 30 घंटे में पूरा होगा।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

वित्त वर्ष के दो माह में ही खजाना खाली क्यों हो गया?

- मार्च 2021 में वित्त विभाग ने जो आकलन विधानसभा में रखे थे वह सही क्यों नही उतरे
- 13 000 करोड़ की अनुपूरक मांगे आने से बजट की विश्वसनीयता कहां बची?
- यह 13 000 करोड़ का खर्च कहां से पूरा किया गया क्या कर्ज लिया गया या टैक्स लगाया गया

शिमला/शैल। वित्तीय वर्ष के तीसरे माह ही सुक्खू सरकार का खजाना खाली हो गया है। आधा दर्जन निगमों बोर्डो और कुछ विभागों के आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन तक नहीं मिल पाया है। हजारों करोड़ का ठेकेदारों का भुगतान रुक गया है। मुख्य सचिव के मुताबिक एक हजार करोड़ का घाटा चल रहा है। इस घाटे को पाटने के लिए 800 करोड़ का कर्ज लिया गया है। जिसके बावजूद दो सौ करोड़ का घाटा चलता रहेगा और परिणामत: इतने भुगतान रुकते रहेंगे। सरकार का आरोप है कि केन्द्र ने प्रदेश की कर्ज लेने की सीमा में 5500 करोड़ की कटौती करके राज्य सरकार के हाथ बांध दिये हैं। इसलिये यह संकट खड़ा हुआ है। केन्द्र सरकार ने कुछ राज्यों की कर्ज लेने की सीमा में कटौती की है। हिमाचल पहले 14500 करोड का कर्ज ले पाता था जो अब केवल नौ हजार करोड ही ले पायेगा। स्मरणीय है कि केन्द्र ने कोविड के लॉकडाउन काल में राज्यों के कर्ज लेने की सीमा में बढ़ौतरी की थी जिसे अब वापस लिया गया है। सुक्खू सरकार ने सत्ता संभालते ही प्रदेश में श्रीलंका जैसे हालत होने की चेतावनी जनता को दी थी। स्वभाविक है कि यह चेतावनी प्रशासन से वित्तीय फीडबैक मिलने के आधार पर ही दी गयी होगी। यह चेतावनी अपने में ही एक असाधारण स्थिति का संकेत थी।

लेकिन क्या सरकार का अपना आचरण इस चेतावनी के मुताबिक रहा है? क्या सरकार ने अनावश्यक खर्चो पर कोई लगाम लगायी? क्या सरकार बनने पर नयी और महंगी गाड़ियां नहीं खरीदी गयी? कितने समय तक तो रिपेयर के काम ही चलते रहे बल्कि इस आश्य के बजट सत्र में विधायक रणधीर शर्मा के प्रश्न के जवाब में यह कहा गया कि अभी सूचना एकत्रित की जा रही है। जब प्रदेश की वित्तीय स्थिति श्रीलंका जैसी होने की आशंका उभर आयी थी तो फिर मुख्य संसदीय सचिवों और करीब आधा दर्जन कैबिनेट रैंक नियुक्तियों का बोझ प्रदेश पर क्यों डाला गया? यह सारे सवाल अब खजाना खाली होने का समाचार बाहर आने के बाद जवाब के लिये खड़े हो गये हैं। क्योंकि खजाना खाली होने का असर किसी मन्त्री या बड़े अधिकारी पर नहीं पड़ेगा। इससे किसी छोटे कर्मचारी/आउटसोर्स कर्मचारी या किसी छोटे अखबार पर व्यवहारिक रूप से पड़ेगा। सरकार पर तो वोट के समय असर पड़ेगा।

सुक्खू सरकार ने जब सत्ता संभाली थी तब प्रदेश के कर्ज और देनदारियों के आंकड़े जारी करते हुए प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करने की बात की थी जो बजट सत्र में नहीं आया। अब जब खजाना खाली होने के समाचार सामने आ गये हैं तब एक बार फिर श्वेत पत्र लाने की चर्चा चल पड़ी है। इसलिये कुछ वित्तीय प्रश्न उठाने आवश्यक हो जाते हैं। नयी सरकार का शपथ ग्रहण 11 दिसम्बर को हुआ 12 दिसम्बर को पिछले छ: माह के फैसले बदले गये। तभी डीजल पर 3 रूपये वैट बढ़ाने का फैसला लिया गया। दिसम्बर से फरवरी तक कई सेवाओं और वस्तुओं के दाम बढ़ाये गये। कर्ज तक लिया गया। जब बजट सत्र शुरू हुआ तो तेरह हजार करोड़ की अनुपूरक मांगे लाकर वर्ष 2022 – 23 के खर्चे पूरे किये गये। उसके बाद वर्ष 2023 – 24 का बजट पारित हुआ। क्या वर्ष 2022 – 23 की अनुपूरक मांगे या वर्ष 2023 – 24 का बजट पारित करते हुये ऐसा कोई संकेत दिया गया था कि दो माह बाद ही खजाना खाली हो जायेगा। क्योंकि जब इतनी बड़ी अनुपूरक मांगे पारित की गयी थी तब यह नही माना गया था कि इससे वर्ष 2022 – 23 के बजट का आकार बढ़ गया है।

स्मरणीय है कि 6 मार्च 2021 को विधानसभा में एफ.आर.बी.एम. प्रावधानों के तहत वर्ष 2024 – 25 तक जो लक्ष्य वित्त विभाग द्वारा प्रस्तुत किये गये थे वह कितने सही निकले हैं इस पर अब कोई सवाल क्यों नहीं उठाया गया है। इन लक्ष्यों के मुताबिक वर्ष 2023 – 24 के लिये राजस्व प्राप्तियां 41438.73 करोड आंकी गयी थी। लेकिन बजट में यह प्राप्तियां 37999.87 करोड़ रखी गयी है यह अन्तर क्यों आया? इसी तरह राजस्व व्यय 43984.32 करोड़ दिखाया गया था जो बजट दस्तावेजों 42704.00 करोड दिखाया गया है जो लक्ष्य से करीब एक हजार करोड़ कम है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वभाविक है कि मार्च 2021 में राजस्व आय और व्यय के जो लक्ष्य सदन में रखे गये थे वह मार्च 2023 में बदल कैसे गये। यही स्थिति वर्ष 2022 – 23 में रही है। वित्त विभाग के आकलनों में इतना अन्तर क्यों आया? क्या इसके लिये कोई जिम्मेदारी तय की गयी? किन विभागों की परफॉरमैन्स लक्ष्यों के अनुरूप नहीं रही है। इसी परिपेक्ष में यह सवाल उठना स्वभाविक है कि वित्त विभाग के वर्तमान आकलनों पर भी कैसे निर्भरता बनाई जा सकती है।

क्योंकि केन्द्र सरकार सितम्बर 2020 से राज्य सरकार को अपने खर्चों में कटौती करने की चेतावनी देती रही है। लेकिन इस चेतावनी को नजरअन्दाज किया जाता रहा। कर्ज लेकर घी पीने को चरितार्थ किया जाता रहा। इस समय सरकार का आउटस्टैंडिंग क़र्ज़ ही जी.डी.पी. का करीब 40% हो चुका है। ऐसे में अब जब कर्ज की सीमा में कटौती कर दी गयी है और सरकार का खजाना खाली चल रहा है तो गारंटीयां पूरी कर पाना बहुत कठिन हो जायेगा। सरकार जिन संसाधनों से संसाधन बढ़ाने के प्रयास कर रही है उनके व्यवहारिक परिणाम इसी कार्यकाल में आ पायेंगे इसको लेकर संदेह व्यक्त किया जा रहा है। माना जा रहा है कि अधिकारियों की ओर से सरकार को सही राय नहीं मिल रही है।

तालिका–I

II. बजट को समझने के लिए मुख्य संकेतक

(₹ करोड़ों में)

		वास्तविक 2021–22	बजट अनुमान 2022–23	बजट अनुमान 2023–24
क.	राजस्व प्राप्तियां			
	(i) राज्य प्राप्तियां	12326.95	13650.60	16472.98
	(ii) केन्द्रीय प्राप्तियां (including Central Taxes) of which	20391.86	19328.79	18130.95
	(a) केन्द्रीय करों में हिस्सा	7349.04	6778.19	8478.02
	(b) केन्द्रीय हस्तांतरण	13042.82	12550.60	9652.93
	(iii) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत अनुदान (excluding CSS Loans)	4590.50	3395.92	3395.94
	योग (राजस्व प्राप्तियां)	**37309.30**	**36375.31**	**37999.87**
ख.	राजस्व व्यय			
	राजस्व व्यय *of which*	36194.54	40278.80	42704.00
	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें	*3483.79*	*2609.04*	*2915.78*
	योग राजस्व व्यय	**36194.54**	**40278.80**	**42704.00**
	निवल (राजस्व घाटा/ लाभ)*	**1114.76**	**–3903.49**	**–4704.12**
ग.	पूंजीगत प्राप्तियां			
	(i) सकल ऋण (excluding W&M / overdraft but includes net PF receipts)	8775.12	11880.02	11839.64
	(ii) ऋणों की वसूलियां	40.72	45.09	26.07
	(iii) विविध पूंजीगत प्राप्तियां	7.01	0.00	0.00
	योग (पूंजीगत प्राप्तियां)	**8822.86**	**11925.10**	**11865.71**
घ.	पूंजीगत व्यय			
	(i) ऋणों की अदायगियां	3343.80	3342.02	3486.64
	(ii) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें	1390.92	787.64	480.91
	(iii) अन्य	5016.43	4956.30	4741.17
	योग पूंजीगत व्यय	**9751.14**	**9085.96**	**8708.72**
	राजकोषीय अधिशेष/ घाटा*	**–5244.86**	**–9602.35**	**–9900.14**

*अधिशेष(+)/घाटा(-)

यह है मार्च 2021 के आकलन

Form-1
(See rule 4 and 5)
Medium Term Fiscal Plan Statement
A. FISCAL INDICATORS – ROLLING TARGETS:

(₹ in Crore)

	Fiscal Indicators	Current year Revised Estimates 2020-21	Ensuing year Target: Budget Estimates 2021-22	Target for next three years Y+1 2022-23	Y+2 2023-24	Y+3 2024-25
1.	Revenue Receipts	35588.36	37027.94	39199.30*	41438.73*	43732.09*
2.	Revenue Expenditure	36010.95	38490.88	41150.40	43984.32	46986.05
3.	Revenue Deficit/ Surplus as percentage of Revenue Receipts	-1.19	-3.95	-4.98	-6.14	-7.44
4.	Fiscal deficit as percentage of Gross State Domestic Product	-4.12	-4.52	-4.67	-4.82	-4.98
5.	Tax revenue as percentage of Gross State Domestic Product	5.06	5.39	5.59	5.79	6.00
6.	Total outstanding Debt as percentage of Gross State Domestic Product	39.33	40.26	40.60	39.91	39.28
7.	Total outstanding Guarantees as percentage of Revenue Receipts	6.07	7.66	Likely to be within FRBM limits.		
8.	Gross State Domestic Product	156522	172174	189392	208331	229164

* GST compensation has been assumed/included in Revenue Receipts beyond June, 2022.

क्या प्रदेश वित्तीय आपात

.....पृष्ठ 1 का शेष

का सारा आरोप सरकार पर लगता जायेगा। अन्त में स्थिति वितीय आपात तक बढ़ जायेगी और तब चयनित सरकार का अपना भविष्य प्रश्निन हो जाता है। राज्यपाल को दखल देने का अवसर मिल जाता है। क्योंकि जब छोटे कर्मचारियों और अन्यों को समय पर वेतन नहीं मिल पायेगा तथा दूसरे भुगतान नहीं हो पायेंगे तो स्थितियां एकदम बिगड़ जायेंगी। प्रभावितों के पास सड़कों पर आने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं बचेगा।

भाजपा स्वभाविक रूप से इस स्थिति को राजनीतिक मुद्दा बनायेगी क्योंकि सरकार को गारंटियां पूरी करनी है जो कर्ज लिये बिना हो नही पायेगी। जब इस सरकार को स्वयं कर्ज लेना पड़ेगा तो भाजपा पर प्रदेश को कर्ज में डूबाने का आरोप स्वत: ही खारिज हो जायेगा। वितीय कुप्रबंधन का आरोप मुख्य संसदीय सचिवों और कैबिनेट रैंक के सलाहकारों की नियुक्तियों में दब जाता है। ऐसे में यदि सुक्खू सरकार ने शीर्ष प्रशासन में जयराम की तर्ज पर परिवर्तन न किये तो सरकार के लिये कार्यकाल पूरा कर पाने तक संकट आ जायेगा